श्री सत्यपाल मलिक : माननीय मंत्री जी से मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आपके मंत्रालय ने बिम्कों, जो मैंचेज बनाने की एक विदेशी कम्पनी है, उस को स्वीडन की एक फर्म से टेक्निकल नौहाऊ इम्पोर्ट करने की इजाजत देने का फैसला किया है । क्या इस मामले में वित्त मंत्रालय और आपके मंत्रालय में कोई मतभेद है ?

SHRI CHARANJIT CHANAl^A: Sir, I require notice for this specific question.

MR. CHAIRMAN: Question No. 45.

Declaration of Purva Anchal As Backward Area

*45. SHRI SYED AHMAD HASHMI; Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the PURVA ANCHAL (Easterin U.F.) comprising ten districts has been declared backward area;

(b) if so, what steps Government propose to take during the Sixth Five Year Plan period for the speedy development of the said area; and

(c) what will be the total financial allocation section-wise in the Sixtli Five Year Plan for this area?

THE MINISTER OF PLANNING AND LABOUR (SHRI NARAYAN DUTT TIWARI): (a) The State Government have included in the Eastern Region 15 districts of which 10 have been identified as industrially backward districts qualifying for •concessional finance from institutions.

(b) and (c) Outlays for the Sixth Tive Year plan of the State have been approved under major sectors of de"-eiopment on the basis of proposals made by the State Government. Dis-aggregation of these outlays for regions/area/districts within the State is done by the State Government.

श्री सैयद अहमद हाशमी : जनाब सद्र, यह सवाल हमदर्दी का भी है, इंसाफ का भी है । हमारे मिनिस्टर साहब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं । टैक्निकल जवाब दे देना बहुत आसान है, और टैक्निकल जवाब मिल गया, लेकिन इस से जाहिर है कि हमारा या उत्तर प्रदेश या खसूसन पूर्वांचल के लोगों को इत्मीनान हो नहीं सकता । बहुत मामूली सी मिसाल है कि अगर कहीं भारी बारिश आई तो सैलाब की तबाहीकारी से वह परेशान और उनका मकान और जरायती जिंदगी का कोई अशिया बाकी नहीं रहता, और अगर सूखा पड़े तो वह कहतकारी का शिका एक-एक दाने से वह मोहताज ।

मान्यवर, हिन्दुस्तान की आजादी के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों ने से हिस्सा लिया । उसमें यू० पी० पीछे नहीं रहा । और पूर्वांचल तो वह हिस्सा है जिसने देश की आजादी के लिए बडी अहम कुर्बानी दी है, लेकिन उस के बावजूद मैं कहूंगा कि आजादी के इन तीस वर्षों में वह डिस्क्रीमिनेशन और इम्तीयाज का शिकार है और मरकजी हुकूमत इस की जिम्मेदार हैं । मैं एक उदाहरण दूं—गाजीपुर पूर्वांचल का वह जिला है जिसमें सन् 1942 के जमाने में यूनियन जैक को उतार कर फैंक दिया और आजादी का परचम लहराया, लेकिन वहां की दशा यह है कि वहीं के रहने वाले आज भी , इस सदी में इस हालत को पहुंच गये हैं कि वह जानवर, भैंस और गाय जो खीद कर देती है उस के अन्दर से दाना चुन कर और उसे धोकर खाते हैं । वह गरीबी की उस रेखा को पहुंच चुके हैं इसलिए कि वहां न कोई इंडस्ट्री है न और कुछ । बावजूद इस बात के कि मरकजी हुकूमत ने डिक्लेयर

किया है ... (**समय की घंटी**) मैं सवाल कर रहा हूं । (**व्यवधान**)

श्री सभापति : सवाल नहीं कर रहे हैं, लैक्चर दे रहे हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : श्रीमन्, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं , गरीब इलाके के रहने वाले हैं, इसलिए ये लोग हल्ला मचा रहे हैं क्योंकि यह नहीं चाहते कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को कुछ मिले ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं सवाल कर रहा हूं । यू० पी० के पूर्वांचल के कुछ जिलों को आपने बैकवर्ड और पसमादा करार दिया है । मैं कहता हूं कि पूरे के पूरे पूर्वांचल को बैकवर्ड करार देना चाहिए । मैंने आपके सामने रखा कि गाजीपुर जिला गरीबी की किस सीमा को पहुंच चुका है, लेकिन उन जिलों के अन्दर गाजीपुर को शामिल नहीं किया गया । इस के बारे में क्या विचार है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जनाब मैं मोहतरीम मैम्बर के ख्यालात की बडी इज्जत करता हूं । उन्होंने यह फरमाया कि मरकजी हुकूमत ने इस तरफ गौर नहीं किया है । मैं उनसे यह अर्ज करना फर्ज समझता हूं कि अगर जो आंकडे हैं, जो वहां के हालात हैं, जो कुछ पिछले मंसूबों के दौरान किया गया है, उन की ओर वे गौर फरमायें तो उन्हें इस बात का तस्कीन होगा कि जो इस बीच किया गया है वह भले ही नाकाफी हो फिर भी ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है । मैं उनकी तवज्जह खास तौर पर दिलाना चाहूंगा शारदा सहायक योजना की ओर जो हमारे मुल्क के सब से बडे सिंचाई के मंसूबों में से है और जिसके द्वारा 40 लाख एकड़ सिंचित जमीन में गाजीपुर, बनारस, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद बगैहर जिले पूर्वी यू० पी० के शामिल हैं । यह इतनी बडी स्कीम है कि उस में पांच पानी हर खेत को मिलने का इमकान है । इसी तरह गाजीपुर में देवकली पंप कैनाल है । देवकली नहर का पहला मंसूबा पूरा हो चुका है , दूसरा मंसूबा हो रहा है । गाजीपुर में एक बडा पुल गंगा पर बनाया जा रहा है। वहां नन्दगंज की चीनी मिल है । ऐसा नहीं है कि कोई तवज्वह नहीं दी गई है ।

मैं यह भी अर्ज करूंगा मोहतरीम मैम्बर से कि यू० पी० का जो छठा मंसूबा है वह 6200 का अभी हाल ही में तय हुआ है और सूबाई सरकार इस बारे में इन्तहा गौर फरमा रही है । हर जिले की स्कीम बन रही है और कारपोरेशन अलग डिविजनों के बन रहे हैं । बनारस डिवीजन का कारपोरेशन-फैजाबाद डिवीजन का कारपोरेशन, गोरखपुर डिवीजन का कारपोरेशन बना है । फिर जो बिजली का ढांचा है उसे मजबूत किया जा रहा है । बिजली के ढांचे को मजबूत करने के लिए—जनाब गौर फरमायेंगे—सिंगरौली का एक बडा थर्मल स्टेशन , जो दो हजार मैगावाट का है, वह पूर्वी यू० पी० में ही बन रहा है, मिर्जापुर में ओबारा में बन रहा है । मैं उनसे अदब के साथ कहूंगा कि मैं मोहतरीम मैम्बर की कद्र करता हूं और वे इस बारे में और भी ब्योरा जानना चाहेंगे तो मैं वह ब्योरा हाजिर कर सकता हूं ।

लेकिन जहां तक छठी योजना का सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको जिलेवार और इलाकावार बना रही है । आप इस बात को मंजूर करेंगे कि जहां हमारा काम, मरकजी हुकूमत का काम बड़े-बड़े 6500 करोड़ वाले

ड्स को मंजूर करना है, वहां ब्यौरेवार मंसूबा सूबाई सरकार ही बना सकती है । मैं समझता हूं कि वह इस बारे में मुझ से सहमत होंगे ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : जनाबेआली, मैं आप के विचारों की कद्र करते हुए भी इस बात पर अपने पूरे इतमिनान का इजहार नहीं कर सकता क्योंकि इस के लिये आप ने कुछ आंकड़े दिये, लेकिन इंडस्ट्रीज की साइड को अगर आप देखें तो आप ने नंदगंज का हवाला दिया । वहां एक शुगर फैक्ट्री बनी है लेकिन उस का कोई कांट्रीब्यूशन नहीं है और कोई दूसरी फैक्ट्री उधर नहीं आयी है । लेकिन मैं आप के माध्यम से एक चीज का और मंत्री जी से जिक्र करना चाहता हूं, खासकर मरकजी सरकार का कि वहां गाजीपुर जिले में एक फैक्ट्री थी, जो इस नेशनल गवर्नमेंट का अहसान नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के जमाने से वह फैक्ट्री वहां चली आ रही है और वहां के मजदूरों की स्ट्रेथ है हजार या डेढ़ हजार । लेकिन आज उस फैक्ट्री को बंद किया जा रहा है और उस को उठा कर नीमच ले जाया जा रहा है और ऐसा होने से जो वहां बेरोजगारों की लिस्ट रोज बढ़ती चली जा रही है उस में मैं समझता हूं कि इस से बहुत ज्यादा सुधार नहीं होगा । आप की इस ओपियम फैक्टरी के हट जाने से वहां की हालत में ज्यादा सुधार नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मरकजी हुकूमत की इस तरफ कोई तवज्जेह है कि अगर उस इलाके में कोई फैक्टरी है, कोई इंडस्ट्री है तो उस को बढ़ाया जाये, उस में मेडिसिन बनाने और दूसरी मुख्तलिफ किस्म की चीजें और शामिल की जा सकती हैं, कारखाने और बन सकते हैं क्योंकि वहीं पर ओपियम भी पैदा होता है, लेकिन इस के बावजूद उस फैक्टरी को वहां से उठा कर ले जाया जा रहा है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस किस्म की हमदर्दी है कि वहां जो चीज पहले से है उस को भी वहां से उखाड़ा जा रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं मोहतरिम मेम्बर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक गाजीपुर से ओपियम फक्टरी को नीमच ले जाने का सवाल है, इस की जानकारी मुझे नहीं है और न इस तरह की किसी फैक्टरी का किसी जगह से हटाये जाने का योजना से संबंध रहता है । लेकिन अगर मोहतरिम मेम्बर चाहेंगे तो मैं इस संबंध में जानकारी करा लूंगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : माननीय मंत्री जी बड़े विद्वान और योग्य व्यक्ति हैं ।

श्री सभापति : जल्दी करिये ।

श्री भा० दे० खोबरागडे : मैं भी एक सवाल पूछना चाहता हूं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : आप ने शारदा प्रोजेक्ट की बात कही । घाघरा का पानी शारदा में डाल कर आप ने मध्य उत्तर प्रदेश को दिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश को नहीं दिया यह भारी बेईमानी हुई है उत्तर प्रदेश के साथ । आप गोलमटोल जवाब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ जो बेइंसाफी हुई है उस को छिपाने की कोशिश मत करिये । मान्यवर, उत्तर प्रदेश ने 12 पावर प्रोजेक्ट सब्मिट किये और आज तक आप ने केवल तीन को स्वीकार किया है और 9 को आप ने फाइल में दबा कर रखा हुआ है । आप कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं । मंत्री महोदय आप वहां की हालात से ज्यादा वाकिफ हैं । दस लाख गरीब मजदूर हर साल वहां से भाग कर पंजाब और हरियाणा आते हैं मजदूरी करने के लिये । यह हालत वहां की है । श्रीमन्, भाखड़ा नंगल बनाया गया, लेकिन घाघरा की बाढ़ को रोकने के लिये आज आजादी के तीस साल हो गये, कोई उपाय केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया और अब उस की कोशिश हो रही है । श्रीमन्, पटेल आयोग की रिपोर्ट को आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया । आप कहते हैं कि हम ने वहां के लिये 6ठी पंचवर्षीय योजना में सब से बड़ा एमाउंन्ट

सेक्शन किया है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री आज भी रो रहे हैं कि केन्द्रीय सरकार उन को रुपया नहीं दे रही है और उन के प्रोजेक्ट नहीं स्वीकार कर रही है । इसलिये मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि उत्तर प्रदेश के जो पावर प्रोजेक्ट सब्मिट हुए हैं 12, उन को आप कब तक स्वीकार करेंगे । नम्बर एक । और नम्बर दो यह कि घाघरा की बाढ़ को रोकने के लिये आप कोई प्रोजेक्ट स्वीकार करेंगे या नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, विद्वान सदस्य ने यह कहा कि शारदा सहायक योजना से पूर्वी अंचल को लाभ नहीं हुआ । इतना समय नहीं है कि इसके विस्तार में जा सकूं, लेकिन उनको अलग से भी हैं यह सूचना दे सकता हूं कि शारदा सहायक योजना से मुख्यतया पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही जिलों को लाभ हुआ है। एम० पी० के दो एक जिले हैं । लेकिन उनको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी शारदा सहायक योजना के दूसरे चरण से बहराइच, गोंडा, बस्ती और उनके पिछड़े हुए जिले गोरखपुर को लाभ हुआ है ।

श्री नागेश्वर प्रताद शाही : वह अभी शुरु हुई है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वह पांचवीं योजना से शुरु हो गया है । श्रीमन्, वह स्वीकार कर रहे हैं कि हुआ है । अब गंडक योजना शुरु हुई है । बाकी जो उन्होंने कहा है कि 12 पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो स्वीकार किये जाने हैं, उनमें से कई स्वीकार हो चुके हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : केवल तीन हुए हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : कौन से नहीं हुए हैं ? श्रीमन्, 12 जो उन्होंने बताया इनमें से कुछ हाइडल के प्रोजेक्ट्स हैं । जहां तक पूर्वांचल का सवाल है उनको स्वीकार किया जा चुका है । इनमें ऊंचाहार और सिंगौली की योजनायें स्वीकार हो चुकी हैं । श्रीमन्, इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट कर दूं कि केवल प्लानिंग कमीशन इसमें अंतिम निर्णय नहीं लेता । पहले ऊर्जा मंत्रालय को निर्णय लेना होता है । मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की दूसरी योजनाओं के सम्बन्ध में, दूसरे प्रोजेक्टस को स्वीकार करने के सम्बन्ध में अपनी ओर से जहां तक हो सकेगा, हम सहानुभूतिपूर्ण निर्णय ले सकेंगे ।

डा० रूद्र प्रसाद सिंह : मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर में अमेठी संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । क्या मंत्री जी अपनी योजना को बनाते समय अमेठी निर्वाचन क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ध्यान रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ अमेठी निर्वाचन क्षेत्र का भी पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा ।

MB. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Implementatioa of the recommendations made by General Purposes Sai-Committee of E.S.I.

*42. PROF. RAMLAL PARIKH: Will the Minister of LABOVR be pleased to refer to the reply to Un^ starred Question 1423 given in the Rajya Sabha on the 4th December, 1980 and state:

(a) what action has been taken by the Government of Gujarat on *each* of the recommendations of the General Purposes Sub-Committee of the E.S.I. Scheme;

(b) what is the extent of the Central Government's respcmsibdlity in